

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 04 अप्रैल, 2017

**विषय:-** नाबार्ड की RIDF-XXII योजनान्तर्गत (फेस-2) के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सारजूला पट्टी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना(पुनरीक्षित) निर्माण कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नाबार्ड की RIDF-XXII योजनान्तर्गत (फेस-2) के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सारजूला पट्टी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 1730/उन्तीस(2)/06-2(30 पे0)/2006 दिनांक 18 अगस्त, 2006 द्वारा रू0 2012.30लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 2130/उन्तीस(2)/16-2(30 पे0)/2006 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा योजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2723.32लाख के आगणन पर टी.ए.सी. वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त (निर्माण कार्य रू0 2471.01लाख, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत रू0 40.89लाख) औचित्यपूर्ण पायी गयी पुनरीक्षित लागत रू0 2596.832लाख(पच्चीस करोड़ छियानवे लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) के सापेक्ष योजना हेतु वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू0 2012.30लाख को कम करते हुए अवशेष लागत रू0 499.60लाख एवं कार्य के सापेक्ष देय सेन्टेज 17% रू0 84.932लाख अर्थात् कुल रू0 584.532लाख(रू0 पांच करोड़ चौरासी लाख त्रेपन हजार दो सौ मात्र) के सापेक्ष नाबार्ड के पत्र दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा मोबिलिजेशन अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी रू0 155.877लाख(रू0 एक करोड़ पचपन लाख सतासी हजार सात सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) शासनादेश संख्या: संख्या: 1730/उन्तीस(2)/06-2(30 पे0)/2006 दिनांक 18 अगस्त, 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- (iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक-निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (viii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (ix) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (x) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- (xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-98-01-नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान(4215-01-102-05 से स्थान्तरित)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु मद के नामें डाला जायेगा।
- 4- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 1704132385 दिनांक 28 अप्रैल, 2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अ० शा० संख्या-22/XXVII (2)/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव।

प०सं० 377(1)/उन्तीस(2)/17-2(30 पे०)/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड़, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
1. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

*Mahavir Singh*  
(महावीर सिंह)

उप सचिव।